should have become bogged down in petty intrigues and administrative bungling. I would urge that the Government of India should immediately move to take over Aurobille as a national memorial of Sri Aurobindo and for this purpose bring a Bill before the Parliament as early as possible.

(iv) SUPPLY OF ESSENTIAL COMMODITIES AT REASONABLE PRICES.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी के साथ बढ़ती जा रही हैं । चीनी, दाल, तेल, साबुन एवं अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में पुनः वृद्धि हो गयी है । चीनी का दाम कहीं-कहीं तो आठ रूपए प्रति किलो हो गया है, जिससे गरीब आदमी तो उसे खरीद भी नही सकता । गुड़ की भी कीमत एक माह के भीतर दुगुनी हो गयी है । बेबी-फड की कीमत प्रायः बढ़ती चली जा रही है । सरकार की वर्तमान आर्थिक नीति में निहित दोष के कारण बढ़ती हुई कीमतों पर नियंत्रण नही स्थापित हो पा रहा है । बहुत सी वस्तुयें जैसे सीमेंट आदि तो उपभोक्ताओ को मिल भी नही पा रही है ।

अतः सरकार को शीघ्र प्रभावशाली कदम उठाने चाहियें जिससे उपभोक्ता वस्तुये सस्ते दामों पर आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सकें । बजट पेश होने के बाद उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि अत्यन्त चिन्ताजनक है । नागरिक आपूर्ति मंत्रालय को तत्काल इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिए ।

(v) NEED TO RESUME RELIEF WORK IN THE TRIBAL AREAS OF JHABUA RATALM, DHAR AND KHARGON DISTRICTS MADHYA PRADESH.

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में झाबुआ रतलाम, धार, खरगोन जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में जहां एक ओर अकाल राहत कार्य बन्द कर दिए गए हैं, वहां दूसरी ओर कई महीनों की मजदूरी का भुगतान उन्हें नहीं किया गया है । साथ ही सस्ते अनाज की दुकानों में आदिवासियों का मुख्य भोजन मोटा अनाज, ज्वार, मक्का आदि उपलब्ध नही हैं । बाजार में ऊंचे दामों में अनाज मिल रहा है, जिसे आदिवासी क्रय नहीं कर सकता है ।

अतः सर्वत्र आदिवासियों में भूखमरी एवं असन्तोष व्याप्त है । राज्य सरकार को निर्देश दये जाये कि जब तक नई फसल नहीं पके तब तक राहत कार्य जारी रखे जायें एवं मजदूरी का अविलम्ब भुगतान किया जाये और शासकीय सस्ते अनाज की दुकानों पर मोटे अनाज की व्यवस्था की जाये ।

(vi) NEED FOR IMMEDIATE SUPPLY OF WHEAT FOR "FOOD FOR WORK" PROGRAME IN RAJASTHAN.

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय खाद्य निगम ने राजस्थान प्रान्त में गेहूं का स्टाक जो उनके गोदामों में जमा कर रखा था, उक्त स्टाक प्रान्त में दस दिन से बिल्कुल समाप्त हो गया है । जिसके कारण राजस्थान प्रान्त में जिला बाड़मेर, जैसलमेर, आदि में अकाल राहत कार्य चलते थे, वह बन्द हो गए हैं । अन्य कार्य जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत चल रहे थे वे सभी बन्द हो गए हैं सस्ते अनाज की दुकानों में प्रान्त भर में गेहूं के न मिलने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भयंकर असन्तोष है । गेहूं के भाव चरम सीमा पर पहुंच गए हैं । अकाल राहत कार्य एवं अनाज के बदले कार्य, फूड फार वर्क नहीं चलने से कुछ जिलों में भुखमरी की स्थिति आ रही है । अतः केन्द्र सरकार तुरन्त राजस्थान प्रान्त में गेहूं का स्टाक जल्दी से जल्दी पहुंचा कर राजस्थान की जनता की आवश्यक मांग की पूर्ति करे ।

(vii) REPORTED VIOLATION OF THE COMPANIES ACT, INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND REGULATION) ACT, FOREIGN EXCHANGE REGULATION ACT, ETC., BY FOREIGN COMPANIES OPERATING IN INDIA.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Mr. Deputy-Speaker, Sir, it has been reported that official inspection has brought out that branches and subsidiaries of Foreign Companies operating in India are violating with impunity the Companies Act, Industrial Development Regulation Act (Licencing), Foreign Exchange Regulation Act and MRTP.

The British companies numbering 319 some time ago were on top of the list in this adventure. Although the number has come down because of FERA compulsion, they have increased the remittances considerably. Their assets are going up by leaps and bounds. In 1973-74, the white money value of their assets was